

प्रेषक,

शैलेश बगौली,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेलकूद निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

खेलकूद अनुभाग

देहरादून : दिनांक 09 नवम्बर, 2016

विषय:— हल्द्वानी स्थित स्टेडियम में इंडोर कॉम्प्लेक्स व हॉस्टल भवन के निर्माण हेतु (एस0पी0ए0) के अन्तर्गत वित्त पोषित योजनाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में भारत सरकार द्वारा अवमुक्त धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद-नैनीताल के अन्तर्गत हल्द्वानी में प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रीय खेल कॉम्प्लेक्स के निर्माण हेतु टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित ₹ 1435.07 लाख (सिविल निर्माण कार्य हेतु ₹ 1135.19 लाख तथा अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार कराये जाने वाले कार्य हेतु ₹ 299.88 लाख) की धनराशि भारत सरकार के पत्र संख्या-M-130-48/27(UTT)2013-SP-N(S), दिनांक 12 मार्च, 2015 द्वारा कार्य हेतु ₹ 1291.56 लाख के केन्द्रांश (वस्तुतः लागत ₹ 1435.07 लाख) पर सहमति प्रदान करते हुये ₹ 585.02 लाख केन्द्रांश अवमुक्त किया गया तथा भारत सरकार के पत्र संख्या-F.No-44(21)/2013-1498, दिनांक 09 मार्च, 2016 द्वारा ₹ 611.58 लाख केन्द्रांश प्राप्त हुआ। इस प्रकार कुल प्राप्त केन्द्रांश की धनराशि ₹ 1196.60 लाख के सापेक्ष राज्यांश के रूप में ₹ 200.00 लाख की धनराशि वित्तीय वर्ष 2014-15 में शासनादेश संख्या-65/VI-2/2015-22(2)/2013-टी0सी0, दिनांक 30 मार्च, 2015, वित्तीय वर्ष 2014-15 में शासनादेश संख्या-297/VI-2/2015-22(2)/2013-टी0सी0, दिनांक 31 मार्च, 2015 के द्वारा ₹ 585.02 लाख की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से, वित्तीय वर्ष 2015-16 में शासनादेश संख्या-260/VI/2016-22(2)/2013-टी.सी., दिनांक 18 मार्च, 2016 के द्वारा ₹ 100.00 लाख की धनराशि एवं वित्तीय वर्ष 2016-17 में शासनादेश संख्या-346/VI/2016-22(2)/2013-टी.सी. दिनांक 27 अप्रैल, 2016 के द्वारा ₹ 33.33 लाख इस प्रकार केन्द्रांश के रूप में ₹ 585.02 लाख एवं राज्यांश के रूप में ₹ 333.33 लाख इस प्रकार कुल ₹ 918.35 लाख की धनराशि उपलब्ध करा दिये जाने के उपरान्त चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रश्नगत कार्य हेतु ₹ 66.67 लाख (छियासठ लाख सड़सठ हजार मात्र) की धनराशि संगत मानक मद से आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

2. उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश सं0-318/XXVII(1)/2014 दिनांक 18 मार्च, 2014 एवं शासनादेश सं0-400/XXVII(1)/2015 दिनांक 01 अप्रैल, 2015 तथा शासनादेश संख्या-490/XXVII(1)/2016, दिनांक 31 मार्च, 2016 में निहित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों एवं अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की

स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। उक्त कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्त विभाग के शासनादेश सं०-474/ XXVII(7)/2008 दि०-15-12-08 के विहित शर्तों के अनुसार कार्यदायी संस्था से निर्धारित प्रपत्र पर एम०ओ०यू० अवश्य हस्ताक्षरित करा लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि मदवार स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।

4. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लो०नि०वि० द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

5. कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली-भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाए।

6. अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर वित्तीय एवं भौतिक प्रगति विवरण शासन को प्रेषित किये जाय तथा समस्त कार्य निर्धारित समय अवधि के भीतर ही पूर्ण किया जाना भी सुनिश्चित किया जायेगा।

7. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-5-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

8. अधिप्राप्ति कार्यों हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

9. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका से करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा। कार्य करते समय टेण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाय। यदि टेण्डर करने में कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति की लागत से कम लागत पर पूर्ण होता है तो ऐसे समस्त बचतों को प्रचलित वित्तीय नियमों का अनुपालन कर राजकीय कोष में जमा कर दिया जाय।

10. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। तथा विलम्ब या अन्य किसी कारण से आगणन किसी भी दशा में पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा। कार्य का गुणवत्ता परीक्षण नियोजन विभाग द्वारा चयनित संस्था से कराये जाने हेतु प्रस्ताव समयान्तर्गत नियोजन विभाग को प्रेषित करते हुए समयबद्ध कार्यवाही की जायेगी।

11- उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-03-खेलकूद तथा युवक सेवा खेलकूद स्टेडियम-102-खेलकूद स्टेडियम-18-विशेष आयोजनागत सहायता-24-वृहत निर्माण कार्य मद के आयोजनागत पक्ष के नामें डाला जायेगा।

संलग्नक: अलाटमेंट आई०डी० संख्या-S161110050, दिनांक : 09 नवम्बर, 2016

भवदीय,

(शैलेश बगौली)
प्रभारी सचिव।

पृष्ठांकन संख्या- 851 /VI/2016-22(2)/2013-टी0सी0, तददिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 खेल मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, नैनीताल।
4. वरिष्ठ वित्त अधिकारी, खेल निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/नैनीताल।
6. बजट राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय सचिवालय, देहरादून।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन।
8. अपर परियोजना प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राजकीय निगम लिमिटेड, हल्द्वानी इकाई, मेडिकल कॉलेज परिसर, रामपुर रोड, हल्द्वानी, नैनीताल।
9. जिला क्रीडाधिकारी, नैनीताल।
10. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव।